नैतिकता, संसदीय आचरण और भारतीय सांसद

द हिंदू

पेपर-II (भारतीय राजव्यवस्था)

पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा आचार समिति की कार्यवाही के परिणामस्वरूप काफी सार्वजनिक बहस हुई है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद, निशिकांत दुबे ने अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई कि सुश्री मोइत्रा ने अपने व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसद में प्रश्न पूछने के लिए एक व्यवसायी से धन प्राप्त किया था। बदले में अध्यक्ष ने शिकायत को जांच और रिपोर्ट के लिए आचार समिति को भेज दिया।

निष्कासन और उदाहरण:

इस बिंदु पर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यदि कोई सांसद संसद में प्रश्न रखने के लिए पैसे लेता है, तो वे विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के दोषी होंगे। ऐसी शिकायतों को जांच के लिए हमेशा विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है। यह समिति उचित जांच के बाद संबंधित सांसद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश के साथ एक रिपोर्ट में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। यदि संसदीय कार्य के संचालन के लिए अवैध परितोषण से जुड़ा मामला साबित हो जाता है, तो सांसद को सदन से निष्कासित भी किया जा सकता है। लोकसभा में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां सांसदों को इस आधार पर सदन से बाहर निकाला गया।

पहले मामले में, 1951 में, प्रोविजनल पार्लियामेंट के एक सांसद, एचजी मुदगल को प्रश्न उठाकर वित्तीय लाभ के बदले में एक व्यापारिक संघ के हितों को बढ़ावा देने और एक विधेयक में संशोधन पेश करने का दोषी पाया गया था, जिसने हितों को प्रभावित किया था। वह बिजनेस एसोसिएशन सदन की एक विशेष समिति ने पाया कि उनका आचरण सदन की गरिमा के लिए अपमानजनक था और उन मानकों के साथ असंगत था जिनकी संसद अपने सदस्यों से अपेक्षा करने का हकदार है। लेकिन सदन द्वारा निष्कासित किए जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया (जिस कार्रवाई की सिफारिश की गई वह उनका निष्कासन था)। 2005 में, एक निजी चौनल के स्टिंग ऑपरेशन में लोकसभा के 10 सदस्यों को संसद में प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेते हुए दिखाया गया था। फिर, एक विशेष समिति नियुक्त की गई जिसने उन्हें एक सदस्य के अनुचित आचरण का दोषी पाया और उनके निष्कासन की सिफारिश की जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया। सभी सांसदों को निष्कासित कर दिया गया. इस प्रकार, सांसदों द्वारा संसदीय कार्य के लिए धन स्वीकार करने की शिकायतें विशेषाधिकार समिति या उस उद्देश्य के लिए सदन द्वारा नियुक्त विशेष समितियों को भेजी जाती हैं। हालाँकि, सुश्री मोइत्रा का मामला आचार समिति को भेज दिया गया है, हालाँकि आरोप संसदीय कार्य करने के लिए अवैध संतुष्टि के बारे में है।

लोकसभा की आचार समिति एक अपेक्षाकृत नई समिति है जिसे 2000 में स्थापित किया गया था, जिसे सांसदों के अनैतिक आचरण से संबंधित हर शिकायत की जांच करने और कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था। इसे सांसदों के लिए आचार संहिता तैयार करने का भी काम सौंपा गया था।

जो अनैतिक है वह अपरिभाषित है:

इस समिति का एक दिलचस्प पहलू यह है कि 'अनैतिक आचरण' शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। आचरण के किसी विशेष कार्य की जांच करना और यह तय करना कि यह अनैतिक है या नहीं, यह पूरी तरह से समिति पर छोड़ दिया गया है। पिछले दिनों तय किए गए कुछ मामले निश्चित रूप से उस प्रकार के आचरण की ओर इशारा करते हैं जिसे अनैतिक कहा जा सकता है। एक उदाहरण में, एक सांसद अपनी करीबी महिला साथी को अपनी पत्नी बताकर संसदीय दौरे पर अपने साथ ले गया। समिति ने सांसद को अनैतिक आचरण का दोषी पाया और उसकी सिफारिश थी कि उन्हें सदन की 30 बैठकों से निलंबित किया जाए। उन्हें उस लोकसभा के कार्यकाल के अंत तक किसी भी आधिकारिक दौरे पर किसी साथी या अपने जीवनसाथी को ले जाने से भी रोक दिया गया था। इस प्रकार, सांसदों की नैतिक अनियमितताएं निश्चित रूप से आचार समिति की जांच के दायरे में आती हैं।

लेकिन कदाचार के अन्य मामले भी हैं जिनकी जांच या तो आचार समिति या विशेष समितियों द्वारा की गई थी। उदाहरण के लिए, एक सांसद ने संसद द्वारा जारी कार पार्किंग लेबल का दुरुपयोग किया। मामले को एथिक्स कमेटी को भेजा गया था, जिसने मामले की जांच के बाद इसे बंद कर दिया क्योंकि सांसद ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। एक अन्य मामले में, एक सांसद अपनी पत्नी और बेटे के पासपोर्ट का उपयोग करके एक महिला और एक लड़के को विदेश दौरे पर ले गया। इसे एक गंभीर मामला माना गया क्योंकि इसमें पासपोर्ट अधिनियम का उल्लंघन शामिल था। यह मामला एक विशेष जांच समिति को भेजा गया जिसने उन्हें गंभीर कदाचार के साथ-साथ समिति की अवमानना का दोषी ठहराया और उनके निष्कासन की सिफारिश की। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गंभीर कदाचार से जुड़े अधिक गंभीर मामलों को या तो विशेषाधिकार समिति या विशेष समितियों द्वारा निपटाया जाता है, न कि आचार समिति द्वारा।

सुश्री मोइत्रा के मामले में, यदि शिकायत उनके द्वारा अवैध परितोषण स्वीकार करने के बारे में है, तो मामला विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला बन जाता है और इसे नैतिकता समिति द्वारा नहीं निपटाया जा सकता है। चूंकि किसी लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेना एक आपराधिक अपराध है, इसलिए इसकी जांच आम तौर पर सरकार की आपराधिक जांच एजेंसियों द्वारा की जाती है। संसदीय समितियाँ आपराधिक जाँच से नहीं निपटतीं। वे सबूतों के आधार पर तय करते हैं कि सांसद का आचरण विशेषाधिकार का उल्लंघन है या सदन की अवमानना है और तदनुसार उन्हें दंडित करते हैं। लेकिन सदन द्वारा सजा का संबंध सदन में उनके कामकाज से है। अन्यथा, वह कानून के अनुसार आपराधिक अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। याद रहे कि जिन 10 सांसदों को लोकसभा से निष्कासित किया गया था, उन पर अभी भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा है।

संसदीय जांच न्यायिक जांच के समान नहीं है। एक न्यायिक निकाय कानून और नियमों के अनुसार किसी मामले की जाँच करता है, और न्यायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। संसदीय समितियों में संसद सदस्य शामिल होते हैं जो विशेषज्ञ नहीं होते हैं। चूँकि संसद के पास कार्यपालिका की जाँच करने की शक्ति है, जो उसके प्रति जवाबदेह है, उसके पास जाँच की शक्ति भी है। इसे अपने सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए अपने सदस्यों सहित अन्य लोगों को दंडित करने की भी शक्ति है।

लेकिन किसी मामले की जांच में संसद द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके न्यायपालिका से भिन्न होते हैं। संसद अपनी समितियों के माध्यम से जांच का काम करती है जो सदन के नियमों के तहत कार्य करती हैं। सामान्य तरीकों में शिकायतकर्ता और गवाहों द्वारा समिति के समक्ष रखे गए लिखित दस्तावेजों की जांच, सभी प्रासंगिक गवाहों की मौखिक परीक्षा, यदि आवश्यक समझा जाए तो विशेषज्ञों की गवाही, समिति के समक्ष रखे गए साक्ष्य की पूरी मात्रा की जांच करना और पहुंचना शामिल है। साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष पर। यदि समिति सदन के किसी सदस्य के खिलाफ शिकायत की जांच करती है, तो वह एक वकील के माध्यम से उसके समक्ष उपस्थित हो सकता है और अध्यक्ष की अनुमति पर शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों से जिरह भी कर सकता है। समिति को उपलब्ध कराए गए सभी साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकाला गया है। अंतिम विश्लेषण में, समिति सामान्य ज्ञान के आधार पर एक दृष्टिकोण अपनाती है। संसद की समिति के निष्कर्ष संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर कहे जा सकते हैं। साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के नियम संसदीय समिति की जांच पर लागू नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति या दस्तावेज के साक्ष्य की प्रासंगिकता का प्रश्न अंततः अध्यक्ष द्वारा ही तय किया जाता है, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार नहीं।

प्रश्नों का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण

सांसदों द्वारा अपना पासवर्ड और लॉगिन विवरण किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करने का मामला अब तूल पकड़ गया है। हकीकत में, सांसदों के पास बैठकर सवाल लिखने का समय नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वे निजी सहायकों के साथ पासवर्ड साझा कर रहे हैं, जिसे एक व्यावहारिक आवश्यकता कहा जा सकता है। इसके अलावा, ऐसा लगता है कि लोकसभा ने प्रश्नों की ऑनलाइन प्रस्तुति को विनियमित करने के लिए कोई नियम नहीं बनाया है। इसके अलावा, एक सांसद अपने संसदीय कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। उन पर उन स्रोतों का खुलासा करने का भी कोई दायित्व नहीं है जहां से उन्हें अपने संसदीय कार्य करने के लिए जानकारी मिलती है। संविधान का अनुच्छेद 105 उन्हें सदन में "कुछ भी" कहने की आजादी देता है। इस अधिकार को संसद में रखे जाने वाले प्रश्न पूछने या विधेयकों या संकल्पों को तैयार करने के लिए जानकारी के किसी भी स्रोत का उपयोग करने तक विस्तारित माना जाना चाहिए। इसलिए, किसी सांसद की जानकारी के स्रोतों की जांच को कानूनी मंजूरी नहीं मिल सकती है। अन्यथा, संसद के पास अपने सदस्यों को अनुशासित करने की शक्ति है।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : लोकसभा में आचार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इसका गठन पहली बार 2000 में किया गया था।
2. इसमें लोकसभा स्पीकर द्वारा नामांकित 10 सदस्य होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to the Ethics Committee in the Lok Sabha:

1. It was first formed in 2000.
2. It consists of 10 members nominated by the Lok Sabha Speaker.

Which of the statements given above is/ are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : a

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : "किसी संसद सदस्य के खिलाफ संसदीय जांच न्यायिक जांच के समान नहीं है।" तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा मामले के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण:

- ❖ उत्तर के पहले भाग में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा मामले की चर्चा करें।
- ❖ दूसरे भाग में संसदीय जांच और न्यायिक जांच में अंतर और इस मामले में प्रश्न में दिए कथन का विश्लेषण कीजिए।
- ❖ अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।